(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें सिक्कों की कमी के संबंध में 1974 में किये गए किसी भी प्रकार के अध्ययन की जानकारी नहीं है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

615. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला संयंत्र द्वारा उत्पादित स्क्रेप का कुछ प्रतिशत उड़ीसा की औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार आरक्षित रखी जाने वाली स्क्रेप का प्रतिशत क्या है और क्या इसका वितरण उक्त राज्य उद्योग निदेशक के माध्यम से किया जाता है ;

(ग) मेल्टिंग स्क्रेप, रीरोलिंग स्क्रेप और औद्योगिक स्क्रेप का कितने-कितने प्रतिशत भाग राज्य की इकाइयों को दिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार यह अनुरोध करती रही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित स्क्रेप उस राज्य में स्थित औद्योगिक एककों को आवंटित किया जाए ;

(ङ) यदि हां, तो भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (कु० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उद्योग निदेशालय की मार्फत उड़ीसा राज्य में औद्योगिक इकाइयों को स्क्रेप के आवंटन में आरक्षित प्रतिशत का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) गलनशील स्क्रेप — कुल वार्षिक उपलब्धि का 22 प्रतिशत

(ii) पुनर्वेलनयोग्य स्क्रेप — कुल वार्षिक उपलब्धि का 35 प्रतिशत

(iii) औद्योगिक स्क्रेप — कुल वार्षिक उपलब्धि का 22 प्रतिशत

(घ) से (च) जी, हां। जनवरी, 1985 में मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि भिलाई इस्पात कारखाना मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के लिए स्क्रेप का उतना अनुपात आरक्षित कर देगा जितना इस समय राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा की इकाइयों के लिए आरक्षित करता है।

इस निर्णय के अनुसरण में भिलाई इस्पात कारखाने ने स्क्रेप के मामले में आरक्षण की प्रक्रिया शुरु कर दी है और "राज्य उद्योग निदेशालय" के परामर्श से वितरण और आवंटन के बारे में विस्तृत विवरण और प्रक्रिया बना रहा है।

हिन्दी में प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम

616. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में किये गए पत्र व्यवहार के संबंध में हुई प्रगति के बारे में वर्ष 1983–84 और 1984–85 के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) प्रत्येक कारखाने में वर्ष 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान उपलब्ध हिन्दी टाइपराइटरों, हिन्दी स्टेनोग्राफरों तथा हिन्दी टाइपिस्टों की संख्या की बाबत तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और

राज्य सरकारों के साथ हिन्दी मे किये गए पत्र-व्यवहार के अलग से आंकडे नही रखे जाते हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिया जाता है।

(ख) इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियंत्रणाधीन उत्पादन-रत इकाइयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

गांजे की खेती

617. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में गांजे की खेती की जाती है और देश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में इसकी खेती की जाती है ;

(ख) क्या सरकार गत दो वर्षों के दौरान गांजे की खेती वाले क्षेत्र में कमी करती रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के खण्डवा (पूर्वी निमाड़) जिले में गांजे की खेती वाले क्षेत्र में कितने हेक्टेयर भूमि की कमी की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय गांजे की काश्त मध्य प्रदेश और उड़ीसा में की जाती है। वर्ष 1984 में कुल 140 हेक्टेयर (अनन्तिम) भूमि में गांजे की खेती की गई थी।

(ख) और (ग) हालांकि काश्त का रकबा, जो 1981 में 226 हेक्टेयर था, वह कम होकर 1983 में 120 हेक्टेयर रह गया था, परन्तु इस में सीमान्तक वृद्धि होने के परिणामतः यह 1984 में 140 हेक्टेयर हो गया।

नारकोटिक औषध-द्रव्य एकल अभिसमय, 1961 के द्वारा लगाई गई अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता के परिणामतः भारत सरकार चिकित्सेतर प्रयोजनों के लिए गांजे की खपत पर 1989 से पाबन्दी लगाने के लिए वचन-बद्ध है। तदनुसार गाँजे की काश्त करने वाले राज्यों से अनुरोध किया गया है कि गांजे की काश्त और उत्पादन में चरण-बद्ध तरीके से उत्तरोत्तर कमी करते रहें।

(घ) निम्नलिखित सारणी से यह द्रष्टव्य है कि उक्त रकबे में वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1983 में कमी हुई थी। तथापि, वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 में उक्त रकबे में कुछ सीमान्तक वृद्धि हुई थी।

वर्ष	हेक्टेयर
1982	142
1983	101
1984	121

अंडमान द्वीपसमूह को मुक्त पत्तन बनाने के बारे में योजनाएं

618. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान द्वीपसमूह को हांग कांग जैसा मुक्त पत्तन बनाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार दीपसमूह में एक मुक्त पत्तन विकसित करने संबंधी संभावना की कुछ समय पूर्व जांच की गई थी। इस मामले मे न तो कोई योजना बनायी गयी है और न ही कोई निर्णय लिया गया है।